मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए करौली को स्वर्ण पदक दिया

भजनलाल ने एचसीएम रीपा संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में पुरस्कार वितरित किये

■ पिछड़े जिलों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2018 से आशान्वित जिला कार्यक्रम शुरु किया गया था। राजस्थान के बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली व सिरोही जिलों को इसमें शामिल किया था। इसी प्रकार 2023 में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉक शामिल किये गये थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचसीएम रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया।

जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के विचारों को समाहित करते हुए आशान्वित जिला और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरूआत की। जिससे अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत प्रदान की जा रही है। शर्मा सोमवार को एचसीएम रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जनवरी 2018 में आशान्वित जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया। वहीं वर्ष 2023 में प्रारम्भ हुए आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सम्पूर्णता अभियान के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया। उन्होंने 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले जिले करौली को स्वर्ण पदक तथा 4 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिलों बारां, धौलपुर, जैसलमेर एवं सिरोही को कांस्य पदक से सम्मानित किया। साथ ही आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले 3 ब्लॉकों जायल (नागौर), रानी (पाली) और खैरवाड़ा (उदयपुर) को स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को रजत, कांस्य एवं ताम्रपत्र श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान सात तत्कालीन जिला कलेक्टर्स को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक्स कार्यक्रमों की क्रियान्विति और इसके सकारात्मक प्रभाव तथा उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस दौरान एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा और आयोजना विभाग में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा सहित संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

न्यायिक कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे

जयपुर, 28 जुलाई। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर गत 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने की घोषणा की है। इसके चलते प्रदेश की 1600 से अधिक अधीनस्थ अदालतों में ठप पड़ा कामकाज वापस पटरी पर लौटेगा।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर संघ ने विधि मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कैडर पुनर्गठन को लेकर जल्दी ही आदेश जारी करने का

■ विधि मंत्री के आश्वासन के बाद 18 जुलाई से चल रहा सामूहिक अवकाश समाप्त करने की घोषणा की।

आश्वासन दिया है। इसके चलते सामूहिक अवकाश को वापस ले रहे है।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिनों एक आपराधिक मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश नहीं होने पर न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी करते हुए अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने और जरूरत पडने पर निलंबन तक करने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने जिला कलेक्टर को भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत की ओर से कठोर रुख अपनाने के बाद कई जिला न्यायिक कर्मचारी संघ काम पर वापस लौट आए थे। वहीं प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ ने भी परिवीक्षा पर चल रहे कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने को कहा था।

पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइन्ड मारा गया

सेना ने ''ऑपरेशन महादेव'' के तहत तीन आतंकवादी मार गिराए

श्रीनगर, 28 जुलाई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये तीन आतंकवादियों में एक आतंकवादी पर्यटक स्थल पहलगाम के बैसरन का कथित मास्टरमाइंड भी शामिल बताया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के दाचीगाम इलाके की ओर बढ़ ने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने इलाके में तलाश अभियान शुरू किया। सेना ने इसे 'ऑपरेशन महादेव' नाम दिया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ शुरू हो गयी। दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में तीनों आतंकवादी ढे र हो गये।

उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा है, जो गत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का कथित मास्टरमाइंड था।

■ सेना के सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पाक आतंकी तथा लश्करे तयैबा का सदस्य सुलेमान शाह उर्फ हाशिम भी था जो गत 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, उस पर 20 लाख रु. का ईनाम भी था।

पहलगाम हमले में एक स्थानीय निवासी और 25 पर्यटक मारे गए थे और भारत तथा पाकिस्तान एक पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुलेमान और दो अन्य के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक एम4 और एके-47 राइफल, ग्रेनेड और अन्य हथियार और गोला-बारुद भी बरामद किया है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी आतंकियों मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस-प्रशासन इस बारे में पूरी जानकारी देगा। मैं सेना, पुलिस और इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। रक्षा सूत्रों के अनुसार, एक हफ्ते पहले सुरक्षाबलों को श्रीनगर के दाचीगाम जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इन आतंकियों ने हमले के बाद पहली बार एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रैस हुए।

इसके बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आज सुबह लगभग 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट के जवानों की एक टुकड़ी ने एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करके आतंकियों का लोकेशन पता लगाया और वहां छिपे तीनों आतंकियों को मार गिराया।

दिव्या देशमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ अगले साल के विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी ही भारतीय बनीं। कोनेरू हम्पी ने भी फाइनल में जगह बनाने के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व कप जीतने तथा कोनेरू हम्पी को उपविजेता बनने के लिए बधाई दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2024 के आम चुनावों में आधार को स्वीकार किया गया था और बिहार में यह व्यापक रूप से उपयोग में है। यह भी तर्क दिया गया कि बिहार जैसे राज्य में, जहाँ गरीबी, अशिक्षा और प्रवासन की दर अधिक है, वहाँ चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र आदि, आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब चुनाव आयोग उन लोगों से भी पात्रता का प्रमाण मांग रहा है, जिन्होंने पहले कई बार मतदान किया है। यदि वे ऐसा प्रमाण देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वालों में थरूर का नाम नहीं

नई दिल्ली, 28 जुलाई। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी से अलग थलग नज़र आ रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कांग्रेस को साफ-साफ कह दिया है कि वह इस मसले पर वही बात कहेंगे जो कहते आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने थरूर से बहस में शामिल होने के लिए

■ चर्चा है कि थरुर ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना से इंकार कर दिया।

कहा था जिसपर उन्होंने कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी लाइन का पालन नहीं कर सकते। उनसे जब संसद परिसर में पत्रकारों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल किया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ कहा मौन व्रत। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने सांसदों की जो सूची जारी की है उसमें गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, सप्तगिरी उलाका तथा बिजेंद्र एस ओला शामिल हैं। सूची में थरूर का नाम नहीं है।

बिजौलियां के तिलस्वां में सड़क पर नाव चली

मांडलगढ़ में तेजपुरा बांध के सभी गेट खोले, गोवटा बाँध में चार फीट की चादर

माण्डलगढ़, 28 जुलाई (निसं)। मांडलगढ़ और बिजौलियां इलाके में पिछले 24 घण्टे से हो रही भारी बारिश से आधा दर्जन नदियां उफ़ान पर चल रही हैं। बिजौलियां के तिलस्वां में बाढ़ के हालात बन गए हैं। रविवार रात को नौ इंच बारिश होने से एरु नदी उफान पर आ गई, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के घरों और दुकानों में तथा सड़कों पर चार से पांच फीट पानी भर गया। लोग छतों पर जाने को मजबूर हो गए। कई लोगों को सड़क पर नाव चला कर रेस्क्यू किया गया। मांडलगढ़ के जेतपुरा बांध के सभी गेट सात फीट तक खोले गए हैं और गोवटा बांध पर चार फीट की चादर चल रही हैं।

मानपुरा गांव की एक बस्ती के घरों में पानी घुस गया। तिलस्वां मंदिर के बाहर कॉलोनी और बाजार जलमग्न होने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा के कलेक्टर जसमीत सिंह सिद्धू ने तिलस्वां और जेतपुरा बांध के हालात का जायजा लेकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

■ मांडलगढ़ में लगातार बारिश के दौर के कारण सड़कों की पुलियाओं पर पानी आ गया। बरुनंदनी, जोजवा, मानपुरा, श्यामपुरा आदि दो दर्जन से अधिक गाँवों का सड़क सम्पर्क टूट गया।

मांडलगढ़ में लगातार बारिश के दौर और नदियों के उफ़ान और कई बांधों की चादर चलने से सड़कों की पुलियाओं पर पानी आ गया है, जिससे बरुनंदनी, जोजवा, मानपुरा, श्यामपुरा सहित दो दर्जन से अधिक गांवों का सड़क सम्पर्क टूट गया है। मैनाली, बेड़च, बनास नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। मांडलगढ़ में श्यामगढ़ के पास नदी बनी पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक ट्रेलर चालक जान जोखिम में डाल कर पुलिया पार कर रहा था और हादसा हो गया। पुलिया के पानी में फिसल कर ट्रेलर नदी में जा गिरा, गनीमत रही कि ट्रेलर का चालक तैर कर बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई।

बिजौलियां के तिलस्वां में भारी बारिश से एरु नदी में उफान आ गया जिससे बाढ़ के हालात बन गये। सड़कों पर चार से पांच फीट पानी भर जाने से सड़क पर नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया।

राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दो बजे तक स्थगित रही

नयी दिल्ली, 28 जुलाई। राज्य सभा की कार्यवाही सोमवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले दूसरी बार दो बजे तक स्थगित की गयी और प्रश्नकाल में भी कोई काम नहीं हो सका। प्रश्नकाल शुरू होते ही कुछ विपक्षी दलों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए शोरगुल शुरू कर दिया था। मानूसन सत्र के पहले सप्ताह राज्य सभा का अधिकांश समय पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मानूसन सत्र के दूसरे सप्ताह आज सुबह शून्य काल में कार्यवाही के बाधित होने के बाद 12 बजे कार्यवाही होते ही विपक्षी दलों के सदस्य अपनी जगह खड़े हो गये और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हंगामा शुरू कर दिया।पीठासीन उपाध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने हंगामा कर रहे सदस्यों कहा कि यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के विषयों के लिए है। इससे पहले सुबह अन्नाद्रुमक के एम धनपाल और आईएस इनबादुरै को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी। दोनों सदस्य उच्च सदन में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे।

'इन-हाउस जाँच में शामिल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डालना, मीडिया ट्रायल, जनता द्वारा न्यायाधीशों का दोष तय करना, ये सब निषिद्ध हैं। अगर प्रक्रिया इसकी अनुमति देती है, तो यह संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन है।''

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र का हवाला दिया जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने पूछा, ''आपको कैसे पता कि उस पत्र में महाभियोग की बात की गई? वह पत्र सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।''

जब सिब्बल ने कहा कि नकदी आउट हाउस से मिली थी और पूछा कि इसका संबंध न्यायाधीश से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो जस्टिस दत्ता ने कहा, ''पुलिस, एफआईआर, स्टाफ - सभी वहां थे और नकदी बरामद हुई।'' सिब्बल ने जवाब दिया कि न्यायाधीश का स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। जब जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या वह यह कह रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है, तो सिब्बल ने कहा, ''हां, नहीं है।''

जस्टिस दत्ता ने पूछा, ''जब समिति गठित हुई थी, तब आपने उसे चुनौती क्यों नहीं दी? आपने इंतजार क्यों किया? अतीत में भी कुछ न्यायाधीश इन कार्यवाहियों से दूर रहे हैं।'' सिब्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा इसलिए समिति के सामने पेश हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि समिति नकदी के असली मालिक का पता लगाएगी। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। जस्टिस वर्मा तब सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली स्थित उनके आवास में आग लगने के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए तीन-न्यायाधीशों वाली समिति बनाई थी। रिपोर्ट आने के बाद सीजेआई ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की।

अब जस्टिस वर्मा ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पैनल की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाने की सिफारिश संसद की सत्ता को हड़पने जैसा है, क्योंकि यह न्यायपालिका को ऐसा अधिकार देता है जो केवल विधायिका के पास है।

उन्होंने कहा, ''यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाने वाले शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायपालिका उस भूमिका को नहीं निभा सकती जो संविधान ने केवल संसद को दी है।''

जैसलमेर स्कूल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलते ही जिला प्रशासन की टीम, उपखंड अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं स्थिति का जायजा लिया। घायल शिक्षक व छात्रा को तुरन्त प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जिला कलैक्टर प्रताप सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

बाराबंकी मंदिर में भगदड़ से 2 की मौत

बाराबंकी, 28 जुलाई। यूपी में बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई।

हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, 29 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि रविवार रात 2.30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक-दूसरे को कुचलते चले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है।

गडकरी द्वारा सरकार के काम काज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुसार, गडकरी की यह नाराज़गी अचानक नहीं है। हाल के वर्षों में उन्हें पार्टी के अहम फैसलों से दूर रखा गया है-2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्हें पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गडकरी की ये टिप्पणियां मोदी सरकार में उनके घटते राजनैतिक महत्व के प्रति असंतोष की झलक हैं, जबकि वे सरकार के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में उनकी कार्यक्षमता और बेबाकी की अक्सर तारीफ होती रही है। ऐसे में उन्हें पार्टी के आंतरिक निर्णयों से अलग रखना स्वयं संघ परिवार के बाहर भी और भीतर भी सवाल खड़े करता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो गडकरी की विचारधारा की जन्मस्थली है, मोदी और शाह की केंद्रीकृत कार्यशैली को लेकर लंबे समय से असहज महसूस कर रहा है। संघ के भीतर से समय-समय पर यह संकेत भी मिलते रहे हैं कि 2014 में मोदी द्वारा तय की गई 75 वर्ष की अनौपचारिक रिटायरमेंट सीमा का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इसी साल 75 वर्ष के हो रहे हैं, और ऐसे में पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

इस पृष्ठभूमि में गडकरी की हालिया टिप्पणी को एक राजनीतिक पहचान की पुन:स्थापना के तौर पर देखा जा रहा है-संभवत: यह भाजपा के भीतर एक वैकल्पिक नेतृत्व संकेत भी हो सकता है।

हालांकि मोदी के नेतृत्व को अभी कोई खुली चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन संघ से गहरे जुड़े एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना यह इशारा हो सकता है कि भाजपा एक ''पोस्ट-मोदी'' (मोदी के बाद) युग की आंतरिक तैयारी की ओर बढ़ रही है।

उच्च न्यायालयों में 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति

नयी दिल्ली, 28 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार उच्च न्यायालयों के लिए 19 न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय की ओर से सोमवार को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुवहाटी के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी की नियुक्ति की गई।

इंगलैण्ड से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिससे भारत की सेवा कंपनियों को बड़ा फायदा होगा।

रणनीतिक रूप से भी यह समझौता भारत की वैश्विक छवि को मज़बूत करता है। इससे भारत अन्य बड़े व्यापार समझौतों, जैसे यूरोपीय संघ, कैनडा और खाड़ी देशों के साथ बातचीत में भी एक मजबूत पक्ष बनकर उभरेगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अनुमानित राजस्व हानि, दीर्घकालिक आर्थिक विकास की तुलना में बहुत कम है। व्यापार और निवेश बढ़ने से भारत का टैक्स बेस भी बढ़ेगा, जिससे आयकर, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स के ज़रिए सरकार की कमाई बढ़ेगी। अत:, जहाँ, जी.टी.आई. द्वारा बताए गए अल्पकालिक नुकसान वास्तविक हैं, लेकिन व्यापार, रोज़गार, निवेश और रणनीतिक स्थिति में होने वाले फायदे कहीं अधिक और स्थायी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने ब्रिटेन से 8.6 अरब डॉलर का माल आयात किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, समझौते के तहत 64 प्रतिशत इम्पोर्ट वैल्यू पर तुरंत टैरिफ हटा दिए जाएंगे, और आगे चलकर यह 85 प्रतिशत टैरिफ लाइनों तक पहुंच जाएगा। हालांकि, कृषि आयात, व्हिस्की और जिन जैसे हाई-टैरिफ आइटम को छोड़कर, अधिकतर अछूते रहेंगे।

वहीं, भारत ने ब्रिटेन को 14.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। इसके बदले में, ब्रिटेन को हर साल 375 पाउण्ड मिलियन (3,884 करोड़) का सीमा शुल्क नुकसान उठाना होगा।

'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी की ट्रंप से कोई बात नहीं हुई'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान यह अधिकृत घोषणा की

■ जयशंकर ने कहा, कुछ देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है, तब भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से आग्रह आना चाहिए तब ही युद्ध विराम पर सहमति बनी।

■ एस. जयशंकर ने कहा, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में गये भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की बातों पर जिस तरह ध्यान दिया गया, उसे भी कूटनीति की उपलब्धियों में शुमार किया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली, 28 जुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का अमेरिका के साथ व्यापार से कोई संबंध नहीं था।

जयशंकर ने लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों नेताओं की बातचीत प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान फोन पर हुई थी। मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कनाडा गये थे।

विदेश मंत्री ने कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ देशों ने कहा था कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है तो भारत की ओर से कहा गया कि यह आग्रह पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) की ओर से आना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ की फोन कॉल आने के बाद ही सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार किया गया और इस पर सहमति बनी।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से सिर्फ तीन देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। यह भारत की सफल कूटनीति का ही परिणाम है।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में गये भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की बातों पर जिस तरह ध्यान दिया गया, उसे भी कूटनीति की उपलब्धियों में शुमार किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में विभिन्न मोर्चों पर भारत की कूटनीति सफल रही है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन द रैज़िसटैंस फ्रंट (टीआरएफ) को अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908